

## डॉ. सुब्बा राव का वक्तव्य, आइएमएफसी वाशिंगटन डी.सी.में वैकल्पिक गवर्नर\*

1. अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आइएमएफसी) की आज की बैठक असाधारण रूप से कठिन और चुनौती भरे समय में हो रही है। वर्ष 2008 की दूसरी छमाही में पूरी तरह से विकसित हुआ वित्तीय संकट स्थावर संपदा गतिविधि के नकारात्मक प्रतिसाद के माध्यम से एक आकार ले चुका है और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरी मंदी में डुबा रहा है। अमरीकी आवासन क्षेत्र में सब-प्राईम संकट के रूप में जो संकट शुरू हुआ था वह अब धीरे-धीरे क्रमिक रूप से वैश्विक बैंकिंग संकट, वैश्विक वित्तीय संकट और एक वैश्विक आर्थिक संकट के रूप में विश्व के तटवर्ती अटलांटिक क्षेत्रों से यूरोप, एशिया- प्रशांत, लैटिन अमरीकी क्षेत्र और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अफ्रीका तक फैल चुका है। यह संकट अब मानव जीवन-निर्वाह तथा कल्याण के क्षेत्र में हाल ही की उपलब्धियों को चुनौती दे रहा है। यह आर्थिक नमनीयता और वित्तीय बाजार स्थिरता संबंधी हमारे बहुत से मौलिक विश्वासों को भी चुनौती देता है।

### वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार

2. आज सबसे ज्यादा अकसर पूछा जानेवाला प्रश्न यह है कि क्या अब सबसे खराब समय आ गया है। यद्यपि कारोबारी विश्वास और उपभोक्ता द्वारा किये जानेवाले खर्च में सुधार के प्रारंभिक संकेत दिख रहे हैं लेकिन बढ़ती बेरोजगारी, इन्वेंट्रियों का ऊँचा स्तर और वित्तीय दबाव समग्र मांग स्थितियों पर भारी पड़ रहे हैं। वित्तीय बाजारों में यद्यपि स्प्रेड सितंबर 2008 के स्तरों से संकीर्ण हो गए हैं लेकिन वे अधिक बने हुए हैं जबकि बैंक क्रेडिट में कमी आई है और अन्य बाजार प्रभावित हुए हैं। बैंकों द्वारा वैश्विक एक्सपोजर संबंधी प्रत्याशित अनुमानों को कम करके लिखा जाना तेजी से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर सभी वित्तीय संस्थाओं के 2007-10 के दौरान कम करके लिखे जानेवाले प्रत्याशित एक्सपोजर अमरीकी आस्तियों के संबंध में 2.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तथा यूरोप और जापान में 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित किये

\* श्री पलानिअप्पन चिदंबरम, सदस्य, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आइएमएफसी) (उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका आते हैं), अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता की ओर से डॉ. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाशिंगटन डी.सी. में 25 अप्रैल 2009 को दिया गया वक्तव्य।

गये हैं। उभरते बाजारों में लोगों को नौकरियों से निकाला जाना समग्र डीलीवरेजिंग को पीछे छोड़ रहा है जो कि शुरू ही हुई है। यह बात पुनर्विन्तयन तथा और तो और जोखिम के बारे में भी गंभीर चिंताएं पैदा कर रही है।

3. आशा की जाती है कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि 2008 की चौथी तिमाही की भांति 2009 की पहली तिमाही में वार्षिक आधार पर 6 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। पूरे विश्व में नीति निर्माण का क्षेत्र स्पष्टतः अनन्वेषित क्षेत्र है। देशों के बीच सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने बड़े, आक्रामक और अपारंपरिक उपायों के बीच इस संकट के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। गिरती मुद्रास्फीति से प्रोत्साहित होकर उन्नत देशों के मौद्रिक प्राधिकारियों ने नीतिगत दरों को अप्रत्याशित रूप से कम कर दिया है और जब क्रेडिट बाजार ढीले होने में फेल हो गए तो केंद्रीय बैंक के तुलनपत्रों का वित्तीय और वित्तीय मध्यस्थों का गारंटियों की दिशा में विस्तार कर दिया गया। स्वचालित बूस्टरों को आगे बढ़ाने वाले भारी विवेकाधीन आवेगों के साथ-साथ राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। यहां तक कि नीतिगत गहनता के वर्तमान स्तरों के साथ 2009 के अंत तक वैश्विक मंदी की द्रोणिका नहीं दिखाई दे रही है और यदि नीतिगत प्रतिक्रियाएं कर्षण की स्थिति प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो यह और आगे भी खिसक सकती है।

4. जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी गहराती जा रही है वहीं उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बाह्य मांग और वस्तुओं के मूल्यों के एकदम से घट जाने, बाह्य वित्तीयन तक पहुंच पर लगाम कसने और पूंजी प्रवाहों में कटौती का धक्का लगा है। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को वृद्धि में 1.5 प्रतिशत की प्रत्याशित मंदी के साथ 2009 में सघट के 1 प्रतिशत के पूंजी बहिर्वाहों का अनुभव होगा। यदि बाह्य वित्तपोषण की कठिनाइयां और बढ़ती हैं, व्यापार और संरक्षणवाद बढ़ता है तथा देशी वित्तीय प्रणालियां उठती और फैलती हैं तो उनकी प्रत्याशाएं वास्तव में और भी खराब हो जाएंगी।

5. ठण्डी होती जा रही मांग और कमजोर होते जा रहे पण्य मूल्यों के साथ पूरे विश्व में मुद्रास्फीति घट रही है, लेकिन फिर भी, यह नौकरियां छूटने की उच्च दर तथा फर्मों के घटते लाभ मार्जिनों के चलते खरीद क्षमता में वृद्धि के रूप में यह बात नहीं बदल सकी है। बहुत सी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह करेंसियों के वास्तविकता से अधिक मूल्यांकन के रूप में परिणित हुई है जो आंशिक रूप से महत्वपूर्ण करेंसियों की आरक्षित राशियों में वृद्धि को दर्शाता है। चूंकि विदेशी मुद्राबाजारों में स्थिरता लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रारक्षित आहरित करके घटा दिए गए हैं अतः, वैश्विक संकट को बर्दाश्त करने वाला कुशन और भी कम हो गया है।

6. वैश्विक रूप से बैंकों द्वारा टॉक्सिक एसेट्स को कम करके लिखने (राइट डाउन) का मौजूदा अनुमान इस आशा पर ज्यादा आश्रित है कि वैश्विक आर्थिक स्थिति और अधिक खराब नहीं होगी। 3 ट्रिलियन अमरीकी डालर के राइट डाउन का केवल एक तिहाई ही पूंजीकृत किया गया है। प्रतिभूति बाजारों के अभी भी कमजोर रहते हुए भारी हानियों संबंधी अनिश्चितता ने वित्तीय बाजारों में स्प्रेड ऊंचे बना रखे हैं और क्रेडिट बाजारों को अभी भी अपनी वास्तविक स्थिति में आना है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौती पुनर्संरचना रणनीति को विश्वसनीयता प्रदान करने की है जो हानि निर्धारण, वास्तविक मूल्यन, तुलनपत्र के साफ सुथरा बनाने और पुनर्पूँजीकरण तथा विपदा समाधान (डिस्ट्रेस रिजोल्यूशन) से बनती है। इन समस्याओं का तेजी से समाधान किया जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार की जड़ें परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में अपने पैर जमा सकें और उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को होनेवाला पूंजी प्रवाह फिर से प्रारंभ हो सके।

### इस निधि की भूमिका और प्रतिक्रिया

7. वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिति में तेजी से आ रही गिरावट ने एक पैमाने पर, मिल-जुले और अवधि

संबंधी संकट का हल निकालने की दिशा में अगुवा राष्ट्रीय प्रयासों को उकसाया है जो कि हालिया इतिहास में संभवतः अप्रत्याशित है। नवंबर 2008 में वाशिंगटन में हुए जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन और इस महीने के शुरू में लंदन में हुए इस सम्मेलन ने एक दिशा दी है और एक अधिक विस्तृत एवं बहुआयामी प्रतिक्रिया तैयार की गई है जिसमें निधियों को आगे रखते हुए तरह-तरह की संस्थाओं का समावेश है।

## चौकसी

8. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अस्तित्व के मूल में इसकी निगरानी की भूमिका है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की निगरानी करती है। इसका कार्य यह मूल्यांकन करना है कि देशों की नीतियां न केवल उनके अपने हितों के अनुरूप हों बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हितों के अनुरूप भी हों। सतत चल रहे संकट ने इसे सुदृढ़ बनाने तथा कोष की चौकसी पर उचित रूप से फोकस करने की प्रासंगिकता और महत्व को रेखांकित किया है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को मैं पुनः दोहराता हूँ - देश जितना ज्यादा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण होगा, चौकसी उतनी ही ज्यादा कठोर होनी चाहिए। समानांतर रूप से बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय चौकसी के बीच का अंतर पाटा जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (अंमुको) की चौकसी से विकासशील देशों की देयताएं नहीं बढ़नी चाहिए।

9. हालांकि कोष का पारंपरिक जोर विनिमय दरों पर रहा है। इस संकट के कारण अंमुको की चौकसी ने समष्टि-वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को बीचो-बीच ला दिया है। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) अधिक से अधिक लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए ताकि इसे द्विपक्षीय चौकसी में प्रभावशाली तरीके से समन्वित किया जा सके। राष्ट्रीय प्राधिकरण अपने वित्तीय क्षेत्रों की

मैदानी वास्तविकताओं के नज़दीक रहते हैं और अंतरराष्ट्रीय रूप से सहमत पद्धतियों पर आधारित विनियामक ढांचे का स्वमूल्यांकन प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसा कि हमने सीखा है, वित्तीय क्षेत्र के मानकों को निर्दिष्ट करना अपने आप में भी संकटों से नहीं बचा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा मानकों की सतत आधार पर समीक्षा की जाए और कार्यान्वयन हेतु अधिकाधिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता रहे। राष्ट्रीय प्राधिकरणों को भी विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक दूसरे की सहायता करने के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की इस समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

10. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करने और उन्हें दूर करने हेतु समयपूर्व चेतावनियों से संबंधित एक ढांचा विकसित करने के संबंध में विस्तारित वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। हम इस सहयोग का स्वागत करते हैं और इस कार्य की संभावित उपयोगिता को स्वीकार करते हुए और भी अधिक विवरणों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, विशेषकर पद्धतियों के संबंध में। सूचना उपलब्धता को सुदृढ़ बनाना इसकी एक पूर्व-शर्त है। इस सहयोग की कारगरता की नियमित रूप से आइएमएफसी द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

## कोष की उधारदात्री भूमिका

11. वित्तीय संस्था के रूप में निधि के पास उधार देनेवाली लिखतें और वित्तपोषण क्षमता होनी चाहिए जिससे कि उधार लेने की संभावित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कोष द्वारा अपने उधार देनेवाले लिखतों और नीतियों में सुधार लाने के लिए किए गए व्यावहारिक और त्वरित उपायों का हम स्वागत करते हैं। लचीली अधिकतम ऋण

सीमा (एफसीएल) और हाई एक्सेस प्रिकॉशनरी स्टैण्ड-बाई अरेंजमेंट्स (एचएपीएस) की शुरुआत समय पर उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। पूर्वानुमानित शर्तबन्दी के अधिकाधिक उपयोग सहित कोष की शर्तबन्दी लागू करने के तौर तरीके को सरल तथा कारगर बनाने से कोष के संसाधनों हेतु सावधानियों सहित सदस्यता की वित्तीयन आवश्यकताओं का ठीक ढंग से संतुलन होगा।

12. इन सुधारों से कोष न केवल भुगतान संतुलन आवश्यकताओं और समष्टि आर्थिक स्थिरता और संरचनागत समायोजनों हेतु बनाए गए कार्यक्रमों के लिए बल्कि इस अनिश्चितता भरे समय में बीमा सुरक्षा के लिए पसंदीदा वित्तपोषक के रूप में पुनः उभरेगा। बहुत से सदस्य देश जो इस संकट के मूल से दूर थे और इस संकट के पैदा करने में उनकी कोई भूमिका या उत्तरदायित्व नहीं था तिस पर भी वे इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कोष को उनकी सहायता करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उभरते बाजारों और विकासशील देशों में इस संकट का पैदा होना नियंत्रित रहे। हम आशा करते हैं कि ये सुविधाएं उचित रूप से लचीलेपन के साथ कार्यान्वित की जाएंगी। कोष को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सदस्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहिए ताकि संकट से बचाव हेतु पहले चरण में और समय पर सहायता प्रदान की जाए। इस संदर्भ में एफसीएल के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्रोत्साहित करने वाली है।

13. हम निम्न आय वाले देशों के लिए वित्तपोषी लिखतों में सुधार लाने के लिए कोष द्वारा उठाए गए कदमों का भी स्वागत करते हैं ताकि उनकी विविध आवश्यकताओं और परिस्थितियों तथा वैश्विक अस्थिरता के प्रति बढ़ी हुई जोखिम बेहतर ढंग से परिलक्षित हो सकें। ऊंचे एक्सेस लेबलों के साथ उचित सावधानी व्यवस्थाएं और कम आय वाले देशों के बीच बढ़िया काम करने वालों के लिए पूर्व शर्त बंदी पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हम इस

कार्य को जल्दी पूरा करने का आहवान करते हैं। बाह्य आघात सुविधा (ईएसएफ) के त्वरित पहुंच घटक सहित रियायती उधार देने हेतु पहुंच सीमाओं को दुगना करना एक अच्छा आंतरिक उपाय है।

14. हम व्यापार वित्तपोषण के बीच के अंतरों को पाटने और व्यापार वित्त प्रवाहों तथा रोल ओवरों हेतु बाजारों में सामान्य स्थिति लौटाने के उन कदमों का भी समर्थन करते हैं जो इस समय चल रहे हैं। एक सच्चे बहु-पक्षीय प्रयास को समर्थन देने के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (आइएफआइ) और द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने के प्रति अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (अं.मु.को) से भी अनुरोध करते हैं। खाद्यान्न, उर्वरक, ईंधन और पूंजीगत माल जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयातों हेतु कम आय वाले देशों को व्यापार वित्तपोषण का अबाधित प्रवाह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

### अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का संवर्धन

15. इस संकट से निपटने के लिए निधि वित्तपोषण हेतु बढ़ती मांग के प्रत्युत्तर में जी 20 देशों के लंदन सम्मेलन ने कोष के पास उपलब्ध स्रोतों को बढ़ाने के लिए किए जानेवाले उपायों पर ठीक ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। इन निर्णयों को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

16. यह कोष एक कोटा आधारित संगठन है और कोटों को ही प्राथमिक व्यवस्था होना चाहिए जिनके माध्यम से अंततः कोष की संसाधन आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आगे आनेवाले मार्ग पर यह दो कार्य करने की मांग करता है। पहला कार्य तो यह सुनिश्चित करना है कि कोटा और मताधिकार सुधार के अप्रैल 2008 पैकेज को शीघ्रताशीघ्र अनुसमर्थन दिया जाए और दूसरा कार्य है कोटों की 14वीं सामान्य समीक्षा को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना और इसे जनवरी 2013 की जगह जनवरी 2011 करना।

इस कोटा समीक्षा का लक्ष्य, कम से कम, कोटा संसाधनों के दुगुना करने पर होना चाहिए। एक समय विभाजित कार्य योजना निर्धारित की जानी चाहिए जो यथाशीघ्र प्रारंभ हो जाए ताकि यह कोटा समीक्षा लक्ष्यित वर्ष में ही और आधी समय सीमा में ही पूरी की जा सके।

17. चूंकि कोटा बढ़ाने और आबंटित करने की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा अतः कोष उधार लेने सहित वैकल्पिक संसाधनों को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। हम इन प्रयासों का समर्थन करते हैं लेकिन इन्हें एक चलताऊ व्यवस्थाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जब तक कि यह कोटा समीक्षा पूरी नहीं हो जाती।

18. हम अब तक पूरी की गई द्विपक्षीय वचनबद्धताओं की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि कोष द्वारा लिए गए उधारों को कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए जो लंदन सम्मेलन के निर्णयों के अनुरूप होने चाहिए। पहला, कोष के उधारों को कोटे में होनेवाली भारी वृद्धि के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरा, कोटा संसाधनों और कोष द्वारा लिए गए उधारों के बीच एक उचित मिश्रण बनाए रखा जाना चाहिए। तीसरा, कोष के उधारों को मोटे तौर पर मौजूदा कोटा हिस्सों, वरीयतः आशोधित एनएबी जैसे बहुपक्षीय ढांचे के भीतर होना चाहिए। चौथा, कोष के संसाधनों में योगदान देने के लिए सदस्य देशों को अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन देने के लिए नोट खरीद व्यवस्थाओं सहित विभिन्न तौर-तरीकों का पता लगाया जाना चाहिए। पांचवां, कोष को उधार दिए गए संसाधनों को देश के अंतरराष्ट्रीय आरक्षितों का एक अंग माना जाना चाहिए।

19. इन तौर-तरीकों के संबंध में जल्द लिए गए निर्णय से सदस्यों के व्यापक समूह से लक्ष्यित संसाधनों का तेजी से संग्रहण हो सकेगा। हमारी ओर से भारत कोष के संसाधनों को बढ़ाने का उत्तरदायित्व लेने के अपने हिस्से का कार्य

करने के लिए तैयार है। एक बार प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार तौर-तरीके तय हो जाएं तो हम अपनी सहभागिता की सीमा तक अपना वचन पूरा करेंगे।

20. हम 250 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के यथा शीघ्र और फ्रंट लोडेड एस डी आर के आबंटनों की मांग करते हैं। इससे विकासशील देशों को लगभग 100 बिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त चलनिधि प्राप्त होगी और उसमें से 19 बिलियन अमरीकी डालर कम आय वाले देशों को जाएगी। स्वैच्छिक करारों के विस्तार के माध्यम से एसडीआर के लिए बाजार को व्यापक और गहन बनाने की आवश्यकता है। एस डी आर आबंटन एक पलटा जाने योग्य उपाय है और जब वैश्विक आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण सुधार दिखाने लगे तो इस आबंटन पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।

21. हम कोष से अपील करते हैं कि वह निम्न आय वाले देशों को रियायती सहायता के लिए ऋण और सब्सिडी दोनों संसाधनों को जुटाने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप प्रदान करे। ढेर सारे उपलब्ध विकल्पों को खंगालने की आवश्यकता है। कम आय वाले देशों को रियायती (सब्सिडाइज) उधार देने का दायरा बढ़ाने हेतु नवीन आय माडल के अंतर्गत सहमत स्वर्ण बिक्री से प्राप्त ऊंचे आगमों के निवेश से अतिरिक्त आय का उपयोग करने के प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। कोष के साथ बहुपक्षीय उधार लेने की व्यवस्था में भाग लेनेवाले सदस्यों के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वह दिए जाने वाले अपने उधारों का एक हिस्सा कम आय वाले देशों के लिए निर्दिष्ट कर सकें। सब्सिडी संसाधनों में दान दाताओं का योगदान बढ़ाने के सघन प्रयास किए जाने चाहिए।

## अभिशासन

22. अभिशासन कोष की वैधता, विश्वसनीयता और प्रभावशालिता के लिए सतत महत्वपूर्ण बना हुआ है।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्रा कोटा और मताधिकार को फिर से तर्कसंगत रूप से जोड़ने (एलाइनमेंट करने) की प्रक्रिया को चालू रखने का है। आगामी कोटा समीक्षा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का व्यापक रूप से पुनर्गठन हो ताकि यह विश्व अर्थव्यवस्था में बदलते आर्थिक भारों को दर्शाए और भावी चुनौतियों के प्रति ज्यादा उत्तरकारी हो। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को कोष में काफी ज्यादा मताधिकार और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जी 20 नेताओं के वाशिंगटन घोषणापत्र में यह सिद्धांत दोहराया गया था और इसका लंदन सम्मेलन में भी समर्थन किया गया था। अब हम आशा करते हैं कि कोटा समीक्षा कोष अभिशासन के व्यापक सुधार के रूप में परिणित होगी।

23. कोष के भीतर आंतरिक अभिशासन सुधार की दिशा में उठाया गया कदम भी प्रासंगिक है, हालांकि इसे कोटा और मताधिकार सुधार का अनुसरण करना चाहिए। अब हमारे पास कंपनी अभिशासन के संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईओ) रिपोर्ट, ट्रेवर मैन्युअल समिति की रिपोर्ट तथा सिविल सोसायटी से प्राप्त इनपुट हैं। हम आशा करते हैं कि इन इनपुटों का गहन विश्लेषण किया जाएगा और निदेशक मंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी तथा कार्रवाई हेतु उचित सिफारिशों की जाएंगी ताकि आइएमएफसी एक ज्यादा प्रभावशाली मंच बने और साथ ही कोष भी मजबूत हो।

24. हम कोष के वरिष्ठ प्रबंधन के चयन हेतु एक खुली, गुण-आधारित प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग करते हैं जो राष्ट्रीयता और भौगोलिक वरीयताओं के निरपेक्ष हो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगला प्रबंध निदेशक इसी ढंग से चुना जाना चाहिए।

### संसदीय क्षेत्र की गतिविधियां

25. अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र की गतिविधियों पर आता हूँ।

### भारत

26. वैश्विक वित्तीय संकट ने भारत की वृद्धि की गति बधित की है। चूंकि अधोगामी जोखिमों उत्पन्न हो चुकी हैं, जीडीपी वृद्धि बीते पांच वर्षों (2003-04) के दौरान औसतन 8.9 प्रतिशत वार्षिक रहने के बाद 2008-09 के लिए 6.5 से 6.7 प्रतिशत की सीमा में रहने का अनुमान लगाया गया है। निजी उपभोग और निवेश व्यय दोनों ही रूपों में घरेलू मांग कमजोर हुई है हालांकि सरकारी अंतिम उपभोग निर्णयात्मक राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों के कारण बढ़ा है। वैश्विक वित्तीय संकट से चलनिधि वित्तीयन और बाजार स्थितियों के बीच चल रही भारी तकरार सामने आ गई है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ने भारत में इस संकट की चुनौतियों के प्रभाव को कम करने में समन्वित और परामर्शी तरीके से इसका प्रत्युत्तर दिया है। रिजर्व बैंक की नीतिगत प्रतिक्रिया का लक्ष्य घरेलू और विदेशी मुद्रा चलनिधि की सुगम स्थिति बनाए रखते हुए वैश्विक वित्तीय संकट की छूट को नियंत्रण में रखना रहा। सरकार ने तीन राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज जारी किए जो ग्रामीण निर्धनों के लिए विस्तारित सुरक्षा जाल कार्यक्रम, फार्म ऋण और माफी पैकेज तथा छोटे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में अदायगी के अलावा आया। इन राजकोषीय उपायों का मिला-जुला प्रभाव लगभग 3 प्रतिशत रहा। रिजर्व बैंक की कार्रवाइयों के चलते वित्तीय प्रणाली से मिलने वाली संभावित प्राथमिक नकदी की संचित राशि जीडीपी का लगभग 7 प्रतिशत है। आगे आनेवाले मार्ग में बहुत सी चुनौतियां हैं: राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों का कार्यान्वयन करना विशेष रूप से जन निवेश बढ़ाना; निजी निवेश मांग को पुनरुज्जीवित करना; राजकोषीय प्रेरक तत्वों को विधिवत ढंग से खोलना; क्रेडिट की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए क्रेडिट का प्रवाह बनाए रखना; पर्याप्त चलनिधि के प्रावधान के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता संरक्षित करना और एक ऐसा ब्याज दर

वातावरण सुनिश्चित करना जो अर्थव्यवस्था को वृद्धि के उच्च पथ पर वापस लौटाने में सहायक हो।

27. आगे चलते हुए, निम्न पण्य मूल्यों के साथ संयुग्मित 2008-09 के दौरान किये गये राजकोषीय और मौद्रिक प्रेरक उपाय घरेलू आर्थिक गतिविधि में स्थिरता लाते हुए पलटाव को एक कुशन प्रदान करेंगे। संतुलित रूप में सामान्य मानसून की संभावना के साथ 2009-10 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 6.0 प्रतिशत रखी गयी है। थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़ द्वारा मापे गये अनुसार मुद्रास्फीति मार्च 2010 के अंत तक लगभग 4.0 अनुमानित की गयी। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कम होती जा रही है हालांकि इसमें तेजी कम है। बहुत सी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से कार्य कर रहे बाजारों और सुदृढ़ वित्तीय संस्थाओं के साथ आघातसह बनी हुई है। समष्टि आर्थिक प्रबंधन ने वित्तीय और वास्तविक दोनों ही क्षेत्रों में बहुत सी अन्य आधुनिक और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष भारत में निम्न अस्थिरता बनाए रखने में सहायता की है।

### श्रीलंका

28. श्रीलंका की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल बाह्य स्थिति को देखते हुए आघातसह थी और इसने 2008 में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तेल और आयात की जानेवाली वस्तुओं के उच्च मूल्य ने समष्टि आर्थिक स्थिरता को संकट में डाला इसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा चौड़ा हो गया और मुद्रास्फीति को तेजी से बढ़ने का मौका मिला। वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल ने पूंजी अंतर्वाहों को उलट दिया जिसके कारण आरक्षित निधि रीतने लगी और बाह्य क्षेत्र में भारी असंतुलन पैदा हो गया। इन चुनौती पूर्ण परिस्थितियों के बावजूद विवेकसम्मत समष्टि आर्थिक नीतियों ने वृद्धि के वेग को समर्थन प्रदान किया जबकि हेडलाईन मुद्रास्फीति जुलाई 2008 के 28.2 प्रतिशत के

उच्च स्तर से उतरकर मार्च 2009 में 5.2 प्रतिशत पर आ गई। राजकोषीय घाटा यथोचित रूप से निम्न स्तर पर बना रहा तथा जीडीपी के सापेक्ष लोक ऋण में लगातार चौथे वर्ष भी गिरावट जारी रही। बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से घटकर 5.2 प्रतिशत पर आ गई जबकि गरीबी पिछले अनेक वर्षों से घटती जा रही है और वर्तमान समय में लगभग 15.0 प्रतिशत पर है। खराब होते जा रहे वैश्विक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में आशा की जाती है कि वृद्धि में तेज गिरावट आयेगी लेकिन यह 2009 में 4.0 प्रतिशत के आसपास बनी रहेगी जिसे समष्टि आर्थिक नीतियों और घरेलू अर्थव्यवस्था में विस्तार विशेष रूप से देश के पूर्वी और उत्तरी देशों में विस्तार से समर्थन प्राप्त हुआ। जैसे ही सामान्य स्थिति बहाल होती है, उच्च वृद्धि के पथ पर आने का आशावाद तथा विकासात्मक प्रक्रिया के ऊपर उठने का आधार मजबूत होता जा रहा है।

### बांग्लादेश

29. बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 2008 की पहली छमाही में खाद्यान्न और वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में अचानक वृद्धि तथा सितंबर 2008 से वैश्विक संकट के फैलने को देखते हुए अच्छी तरह से खड़ी रही। आशा की जाती है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2008-09 (जुलाई-जून) में 6.0 प्रतिशत के आसपास रहते हुए सुदृढ़ बनी रहेगी जिसे वर्ष की दूसरी छमाही में अनुकूल कृषि निष्पादन तथा खाद्यान्न, ईंधन और वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट का लाभ प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप आपूर्ति प्रबंधन और मौद्रिक-राजकोषीय नीति के योग द्वारा सुदृढ़ हुई मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष आधार पर गिरकर एक वर्ष पहले के 11.4 प्रतिशत से जनवरी 2009 में 6.1 प्रतिशत पर आ गई। कर राजस्वों में होने वाली वृद्धि लक्ष्य से कम रहने के कारण लोकवित्त कुछ दबाव में आ गए जिसे दुलमुल मांग तथा निम्न वार्षिक विकास योजना उपभोग के कारण व्यय में कमी के द्वारा संतुलित किया जाता रहा है। गहराता जा रहा वैश्विक

## भाषण

डॉ. सुब्बा राव  
का वक्तव्य,  
आइएमएफसी वाशिंगटन  
डी.सी.में वैकल्पिक गवर्नर

पलटाव जो प्रमुख निर्यात बाजारों को प्रभावित कर रहा है, उसके कारण बांग्लादेश का भुगतान संतुलन कुछ दबाव में आ गया है और साथ ही विप्रेषणों के कुछ धीमे हो जाने से उग्र हो गया है हालांकि वे अभी भी अच्छी तरह से वैसे ही मजबूत बना हुआ है। सकल अंतरराष्ट्रीय आरक्षित फरवरी 2009 के अंत में 5.9 बिलियन अमरीकी डॉलर रहे जो कि लगभग तीन महीने के आयातों के बराबर है। बांग्लादेश ने व्यापार संरक्षणवाद और स्पर्धात्मक अवमूल्यों से बचते हुए बहुपक्षीय ढांचे के अंतर्गत मौजूदा संकट से निपटने के समूह-20 देशों के निर्णयों का भी स्वागत किया है। बांग्लादेश एक संतुलित प्रेरक पैकेज के साथ इस संकट को दूर करने का भरसक प्रयास कर रहा है जिसका लक्ष्य ग्रामीण, कृषि और बुनियादी संरचना क्षेत्र में निवेश के साथ घरेलू मांग को तेज करना, निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा देना, खाद्यान्न और सामाजिक सुरक्षा उपायों को पुष्ट करना तथा अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रमों को प्रारंभ करना है।

### भूटान

30. भूटान में वर्ष 2008 ऐतिहासिक महत्व के क्षणों का वर्ष था जब देश ने नयी प्रजातंत्रिय संस्थाओं के साथ संवैधानिक राजशाही में कदम रखा। यह विकास ऐजेंडा के कार्यान्वयन हेतु पृष्ठभूमि प्रदान करता है। दसवीं योजना हेतु वित्तपोषण जिसका लक्ष्य औद्योगिक विकास के माध्यम से गरीबी में कमी लाने, संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि और बुनियादी संरचना निवेश पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ विकास पर होने वाले खर्च को दुगना करना है। 2007-08 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 21.4 प्रतिशत थी जो ताला जल परियोजना तैयार होने के साथ-साथ जल विद्युत उत्पादन क्षमता को दुगना करने को दर्शाता है। आशा की जाती है कि जीडीपी की वृद्धि दर 2008-09 में 5.6 प्रतिशत के प्रवृत्ति स्तर पर वापस लौट आयेगी। पड़ोसी देशों विशेषरूप

से भारत और बांग्लादेश के साथ बढ़े हुए व्यापार संबंधों के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण वृद्धि और विविधीकरण में सहायता दे रहा है। बाह्य क्षेत्र के संबंध में जहां परिवर्तनीय करेंसी के आरक्षित सुगम हैं वहीं आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रुपया आरक्षितों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन अपेक्षित है।

### निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

31. इस संकट ने विश्व के सामूहिक नेतृत्व और बहुपक्षीय संस्थाओं की कुशलता और प्रासंगिकता को कसौटी पर रख दिया है। हम एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जिसने समस्त विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है चाहे वह मूल में हो या परिधि में हो। यह निरुत्साहकारी लेकिन अलंघ्य नहीं, चुनौती के प्रति एक त्वरित और अंतरराष्ट्रीय रूप से समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर काफी कुछ निर्भर करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इस प्रयास के केंद्र में है और सुधार का मार्ग प्रशस्त करने में इस कोष की भूमिका में हम सबका अपना-अपना हिस्सा है। परिणाम देने में कोष की क्षमता अंततः इस बात से जुड़ी है कि हम इसे संसाधनों, बेहतर अभिशासन, पहले से अधिक जिम्मेदारी से कितना और कितनी शीघ्रता से तथा पुनर्परिभाषित अधिकार के साथ शक्ति प्रदान कर सकते हैं जिससे कि यह बदलते विश्व की आवश्यकताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भीतर भी एक तत्काल आमूलचूल दृष्टिकोण, संस्कृति और रणनीति में शीघ्र परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि यह अपने विगत और अविश्वसनीयता को स्वयं ही छोड़ सके जो इसके साथ चलती है। इस संकट के बाद जो विश्व उभरेगा उसमें इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि वह पहले जैसा नहीं रहेगा और चुनौती यह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को फिर से ऐसा बनाया जाए ताकि यह भविष्य में पहले से ज्यादा प्रासंगिक, उपयोगी और कारगर बने।